भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4043

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएलआई योजना के अंतर्गत सोलर पीवी विनिर्माताओं हेतु चयन प्रक्रिया</u>

4043. श्री दुष्यंत सिंहः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च दक्षता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम "सौर पीवी मॉड्यूल पीएलआई योजना" का ब्यौरा क्या है और इस योजना का सौर ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण क्षमता को किस प्रकार बढ़ाने का लक्ष्य है;

(ख) क्या सरकार ने पीएलआई योजना के अंतर्गत सोलर पीवी विनिर्माताओं के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया अपनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन से विशेषकर रोजगार सृजन, आयात प्रतिस्थापन और निवेश प्रवाह के संदर्भ में क्या आर्थिक प्रभाव अपेक्षित हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने और आयातित सोलर मॉड्यूल पर निर्भरता कम करने हेतु पहलें की हैं, जिससे भारत के सौर क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए आबंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं।

(ख) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत निर्माताओं का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

(ग) और (घ): सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, इस योजना के तहत 73,400 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 17,200 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है। दिनांक 28.04.2021 को एमएनआरई ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रांश-I) के लिए पीएलआई योजना के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए। वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डेटा बैंक से संबंधित वेबसाइट के अनुसार, भारत में सौर मॉड्यूल आयात वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 3,363 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 994 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि सोलर मॉड्यूल निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 83 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1051 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो सौर विनिर्माण में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

*****